मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

'आप' के हाथों बिके दो कांग्रेसी पार्षद 2
अस्पताल में घूसखोरी रैकेट चला रहा है सर्जन डॉ. मनीष रावत 4
काकोरी के अमर शहीदों को लाल सलाम 5
अम्बेडकर और सावरकर भारतीय राजनीति के विपरीत ध्रुव 6
आलीशान क्रिकेट स्टेडियम का सत्यानाश 8

वर्ष 37 | अंक 5 | फरीदाबाद | 18-24 दिसम्बर 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

बड़खल झील को सीवर के बजाय बरसाती पानी से भरेंगे उपायुक्त विक्रम

फ़रीदाबाद (म.मो.) बड़खल झील को लेकर पहली बार किसी अधिकारी ने कोई अक्ल की बात कही है। उपायुक्त विक्रम ने 14 दिसम्बर को इस झील एवं इसके आसपास के क्षेत्र को देख कर कहा कि इसे प्राकृतिक स्रोत यानी कि बरसाती पानी से भरा जायेगा। यह न तो कोई मुश्किल काम है और न ही महंगा। 20-25 वर्ष पहले तक यह झील बरसाती पानी से न केवल लबालब होती थी बल्कि अतिरिक्त पानी को बाहर भी छोड़ा जाता था।

उपायुक्त विक्रम ने भी शायद इसी समझ के आधार पर उक्त बयान जारी किया है। उन्होंने बंद हो चुके उन नाले-नालियों को भी देखा जिनके रास्ते झील में पानी आया करता था। पहाड़ में अंधाधुंध खनन करने व रास्ते आदि बनाने के चलते वे सब नाले-नालियां बंद हुई पड़ी हैं। जिस दिन से इन रास्तों से झील में पानी आना बंद हुआ था, उसी समय यदि शासन-प्रशासन इसकी सुध ले लेता तो इतने वर्षों तक झील की ये दुर्दशा न हुई होती।

इस मसले को लेकर 'मज़दूर मोर्चा' ने अनेकों बार शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का असफल प्रयास किया है। जो बात अब उपायुक्त विक्रम कह रहे हैं इसी बात को पूरे विवरण के साथ 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा बार-बार प्रकाशित किया जाता रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा प्रशासन

कोई भी वह काम नहीं करना चाहता जो मुफ़्त में या सस्ते में हो जाये। किसी काम का जब तक लम्बा-चौड़ा बजट न बने तो भ्रष्ट अधिकारी काम करने को राजी नहीं।

'मज़दूर मोर्चा' के 20-26 जून-2021 के अंक में **'बड़खल झील का स्थाई सत्यानाश करने हेतु 83 करोड़ का बजट'** शीर्षक से प्रकाशित किया गया था (देखें पेज 2)। तब देश के करीब दो दर्जन पर्यावरण-विदों ने करीब दो दिन तक झील एवं इसके आस-पास का सर्वेक्षण करके निगम अधिकारियों को मौके पर बुला कर अपनी सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अधिकारियों के साथ उस वक्त इलाके की विधायक सीमा त्रिखा भी मौजूद थीं। लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट के अंत में उन पर्यावरण-विदों के संगठन ने कहा था कि यदि प्रशासन चाहे तो वे बिना कोई पैसा लिये इस झील को बरसाती पानी से, अगले एक-दो साल में न केवल भर सकते हैं बल्कि कभी सूखने भी नहीं देंगे।

लेकिन ऐसा बढ़िया प्रस्ताव लुटेरे अफसरों व नेताओं को भला क्यों रास आने लगा? उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। इसके बदले 35-40 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसके द्वारा शहर के शोधित सीवेज पानी से इसे भरा जायेगा। इन अफसरों द्वारा शोधित जल के सड़े हुए नमूने आसानी से इसी शहर में उपलब्ध हैं। कैसे कोई विश्वास कर सकता है कि बड़खल झील में डाला जाने वाला जल, उन नमूनों से बेहतर होगा?

स्थानीय सांसद एवं मंत्री कृष्णपाल ने बीके अस्पताल में लगाया मजमा

फ़रीदाबाद (म.मो.) सड़कों पर मजमा लगाने वाले कुशल मदारी को इस काम के लिये किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। परन्तु कृष्णपाल गूजर जैसे सरकारी मदारी बिना सरकारी सहायता के अपना मजमा भी नहीं लगा सकते। इसके लिये भी इन्हें पूरे सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है। दिनांक 12 दिसम्बर को गूजर जी ने अपनी सरकार का प्रोपेगंडा करने के लिये बीके अस्पताल में एक मजमा लगाया।

अपनी व अपनी सरकार की झूठी उपलब्धियां व झूठे ख्वाब दिखाने के लिये लगाये गये मजमे में भीड़ जुटाने के लिये गोल्डन कार्ड वितरण का बहाना बनाया गया। इसके लिये न केवल शहर भर से बल्कि आस-पास के गांवों तक से लोगों को बुलवाया गया। जो कार्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों द्वारा उनके गांवों में ही वितरित किये जा सकते थे, उनके लिये भी दूर-दूर से लोगों को मंत्रीजी के मजमे में हाजिर होने को मजबूर किया गया। इनमें सामान्य नागरिकों के अलावा सरकारी विभागों विशेषकर स्कूलों आदि में कार्यरत छोटे कर्मचारी भी शामिल थे। ये लोग अपना काम-धंधा छोड़कर मंत्रीजी के मजमे में हाजिरी देने पहुंचे।

झूठ बोलने में माहिर भाजपाई कैडर के लोगों ने उन अनेकों लोगों को भी भीड़ बढ़ाने के लिये बुला लिया जिनके नाम कार्ड वितरण लिस्ट में नहीं थे। उन्हें कहा गया था कि यदि वे मंत्री के मजमे में पहुंचेंगे तो उनका नाम भी दर्ज करके लाभर्थियों की सूची में शामिल करा दिया जायेगा। लेकिन न तो नाम दर्ज हुआ और न ही लाभार्थी होने का कोई कार्ड उन्हें मिल पाया। अतत: अपना दिन खराब करके घर के बुद्धू घर को लौट आये।

खट्टर स्वास्थ्य योजनाओं की खुलने लगी है पोल

फ़रीदाबाद (म.मो.) प्रोपेगंडे के बल पर फैलाया गया झूठ आखिर कब तक लोगों को बहलाये रखेगा? ढकोसलों की पोल तो खुलनी ही थी, सो खुलने लगी है। कभी आयुष्मान, उसका गोल्डन कार्ड, अंत्योदय योजना तो कभी चिरआयु आदि योजनाओं के द्वारा लगातार बहकाते आ रहे खट्टर की पोल अब सबके सामने खुल रही है।

इन योजनाओं के तहत स्थानीय बादशाहखान अस्पताल में सैंकड़ों मरीज प्रति दिन जांच हेतु आ रहे हैं। खट्टर के इस अस्पताल में न तो ढंग की लैबोरेट्री है और न ही जांच के लिये सम्बन्धित साजो-सामान। ले-दे कर खून की जांच से केवल हीमोग्लोबिन तथा ब्लड ग्रुप का पता लग सकता है। शेष अन्य जांचों के लिये तो अस्पताल के बाहर लगी दुकाने हैं।

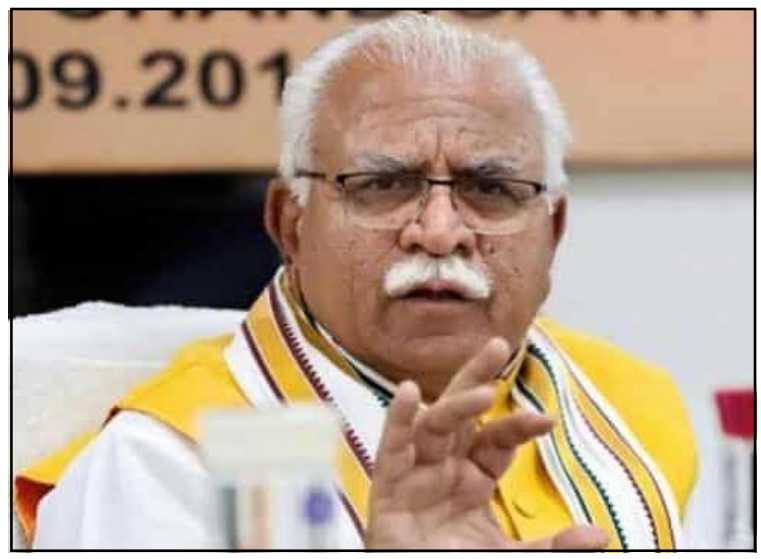

अस्पताल में आने वाले लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन, कार्ड पर पर्ची चिपकाने जैसी तमाम लिफाफेबाजियों के बावजूद किसी भी मरीज़ को मिलता कुछ भी नहीं है और न ही मिलने की कोई सम्भावना नज़र आती है। अस्पताल में दवाईयों की बात तो छोड़िये छोटी-मोटी मरहम-पट्टी तक कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जाहिर है ऐसे में उम्मीदों से मुंह धोकर आये लोगों का भ्रम काफूर होना तय है। ऐसे में लोग सरकार, खासकर स्थानीय विधायकों और मंत्रियों को कोसते व गालियां निकालते हुए देखा जाता है।

हां, इससे वे लोग जरूर संतुष्ट होने का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें पूरी भाग-दौड़ तथा छुटभैये नेताओं की चापलूसी के बावजूद किसी प्रकार का 'लाभार्थी' होने का तगमा नहीं मिल पाया था। 'मज़दूर मोर्चा' इस बाबत गतांक में लिख भी चुका है कि थोड़ा इंतजार करो, लाभार्थी के रूप में भांति-भांति का कार्ड लिये घूमने वाले ये लोग भी रोते-पीटते नज़र आयेंगे।